बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 181 ● नई दिल्ली ● सोमवार 04 मई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद पवन खेड़ा का दिल्ली में भव्य स्वागत, बोले- संविधान जीता, दमनकारी मशीनरी हारी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने संविधान और न्यायपालिका के प्रति अपना अटूट विश्वास दोहराया। यह पूरा मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी से जुड़े कथित मानहानि और जालसाजी के आरोपों से संबंधित है, जिसमें कोर्ट ने खेड़ा को बड़ी राहत दी है।अग्रिम जमानत मिलने के बाद जब पवन खेड़ा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, तो वहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले को संविधान की जीत बताया। खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब भी सरकार अपनी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर किसी नागरिक के अधिकारों को दबाने की कोशिश करती है

स्वतंत्र पत्रकारिता पर खतरा? खरगे का आरोप-सरकार के खिलाफ लिखने वालों को सज़ा, पक्ष में रहने वालों को इनाम

नई दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि उनका संदेश स्पष्ट है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को दंडित किया जाएगा और सरकार के हिसाब से चलने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की सूची गिर रही नीचे

खरगे ने आरोप लगाया कि मीडिया के एक वर्ग को सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की बात दोहराने तक सीमित कर दिया गया है, जबकि सवाल पूछना जारी रखने वालों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। खरगे ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति 2014 से लगातार गिरी है।

संघ परिवार ने समाचार कक्षों को चुप कराने कानूनी ढांचों का इस्तेमाल किया

उन्होंने आरोप लगाया कि संघ परिवार ने समाचार कक्षों को चुप कराने के लिए कानूनी ढांचों का हथियार के रूप में तेजी से इस्तेमाल किया है। खरगे ने कहा कि देश को इस कठोर और निर्विवाद वास्तविकता का सामना करना होगा कि भाजपा के शासन में 2014 से विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति लगातार गिरकर 157वें स्थान पर पहुंच गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर कहा, सही अर्थ में स्वतंत्र प्रेस का काम सरकार की बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना या उसकी नाकामियों को छिपाना नहीं होता। उसका काम सत्ता से सवाल करना, सत्ता की पड़ताल करना और पद पर बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराना है।

पत्रकार सार्वजनिक सत्य के संरक्षक

खरगे ने कहा कि मीडिया सत्ता और लोगों के बीच लोकतांत्रिक संतुलन को बनाए रखता है। उन्होंने कहा, पत्रकार सार्वजनिक सत्य के संरक्षक होते हैं। पंडित नेहरू ने कहा था, प्रेस की स्वतंत्रता केवल एक नारा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक

आवश्यक गुण है। मौजूदा शासन में यह आवश्यक गुण गंभीर रूप से कमजोर हुआ है। खरगे ने कहा, संघ परिवार ने समाचार कक्षों को चुप कराने के लिए कानूनी ढांचों को हथियार के रूप में तेजी से इस्तेमाल किया है। मानहानि कानूनों, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रावधानों और व्यापक आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल न्याय के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि डराने-धमकाने के औजार के रूप में किया जा रहा है।

भाजपा-शासित राज्यों में पत्रकारों की हत्या की जा रही है

उन्होंने दावा किया कि 2014 से 2020 के बीच 135 से अधिक पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया या उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि 2014 से 2023 के बीच 36 पत्रकारों को जेल में डाला गया। खरगे ने कहा कि कई पत्रकारों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) जैसे कठोर कानूनों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा, इस बीच, हिंसा और दंडमुक्ति का एक कहीं अधिक चिंताजनक चलन सामने आया है। भाजपा-शासित राज्यों में पत्रकारों को अपना काम करने के लिए हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र बाजपेयी, छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्राकर, उत्तराखंड में राजीव प्रताप सिंह और हरियाणा में धर्मेंद्र सिंह चौहान-ये सभी भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज वे सत्ता के सामने सच बोलने की भयावह कीमत के कड़वे उदाहरण बनकर खड़े हैं।

स्वतंत्र पत्रकारिता को दंडित किया जाएगा- भाजपा-आरएसएस का संदेश

खरगे ने दावा किया कि भाजपा-आरएसएस सरकार अपने मौजूदा नियंत्रण से संतुष्ट नहीं है और पूर्ण प्रभुत्व की चाह में अब सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रही है ताकि उसे भी चुप कराया जा सके। उन्होंने कहा, भाजपा-आरएसएस का संदेश स्पष्ट है- स्वतंत्र पत्रकारिता को दंडित किया जाएगा और सरकार के अनुरूप चलने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। मीडिया के एक वर्ग को सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की बात दोहराने तक सीमित कर दिया गया है, जबकि सवाल पूछना जारी रखने वालों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है।

सरकार को उच्चतम मानकों को बरकरार रखना चाहिए

खरगे ने कहा, जब हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो यह सभी पक्षों के लिए गहन आत्ममंथन का समय है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता में बैठे लोगों को दीर्घकाल से स्थापित लोकतांत्रिक मानकों को हमेशा बनाए रखना चाहिए। खरगे ने कहा, यदि इन सिद्धांतों से विचलन को लंबे समय तक जारी रहने दिया गया, तो उसके सामान्य और स्वीकार्य बन जाने का खतरा रहता है। इससे लोकतांत्रिक मानदंडों, मूल्यों, संस्थाओं और लोगों को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। खरगे ने कहा कि इसलिए मौजूदा सरकार को उच्चतम संभव मानकों को बरकरार रखना चाहिए।

विपक्ष भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला कर रहा, किरने रिजिजू बोले

नई दिल्ल । देश की राजनीति में इस समय भारी घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि विपक्ष देश की अहम संस्थाओं को निशाना बना रहा है और यह सीधे तौर पर भारतीय लोकतंत्र पर हमला है। रिजिजू का यह सख्त बयान ऐसे समय में आया है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने भारी गड़बड़ियों के चलते कई जगहों पर फिर से वोटिंग कराने का बड़ा फैसला लिया है। बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा और टीएमसी के बीच पहले से ही भारी तनातनी चल रही है। किरेन रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा है कि विपक्ष ने हर उस लोकतांत्रिक संस्था पर सवाल उठाए हैं, जिन पर देश का भरोसा टिका है। रिजिजू ने विपक्ष को चेतावनी दी है कि भारत की आम जनता यह सब देख रही है और वह समय आने पर उन्हें इसका करारा जवाब जरूर देगी। वहीं, बंगाल में चल रहे मतदान के दौरान हुई अप्रिय घटनाओं ने इस राजनीतिक विवाद को और बढ़ा गरमा दिया है। चुनाव आयोग के कड़े फैसलों और भाजपा नेताओं की लगातार शिकायतों के बाद वहां का माहौल पूरी तरह से आक्रामक हो गया है। रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सभी विपक्षी दलों ने सरकारी एजेंसियों, ईवीएम, चुनाव आयोग और मीडिया पर लगातार हमला किया है। उनका कहना है कि अब विपक्षी दल देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को भी अपना निशाना बना रहे हैं। रिजिजू ने कड़े शब्दों में कहा कि विपक्ष को यह एहसास ही नहीं है कि वे ऐसा करके सीधे भारतीय लोकतंत्र के मूल आधार पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत के लोग सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और वे जल्द ही विपक्ष को जिंदगी भर याद रहने वाला सबक सिखाएंगे। रिजिजू का यह बयान चुनाव आयोग के उस कड़े फैसले के बाद आया है, जिसमें फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को दोबारा वोटिंग कराने को कहा गया है।

उत्तम नगर में एमसीडी का बड़ा एक्शन, हस्तसाल कॉलोनी के 19 अवैध ढाबे सील; मचा हड़कंप

पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के पश्चिम जोन के जन स्वास्थ्य विभाग ने अवैध रूप से चल रहे ढाबों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए कल उत्तम नगर स्थित हस्तसाल पुनर्वासित कॉलोनी के विभिन्न हिस्सों में चल रहे 19 ढाबों को सील कर दिया। ये ढाबे कॉलोनी के ए, बी व सी ब्लाक में नियमों को ताक पर रखते हुए संचालित हो रहे थे। निगम का कहना है कि इनमें से किसी भी ढाबे के पास स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस नहीं था। इस कार्रवाई की रूपरेखा पिछले महीने ही तैयार कर ली गई थी। 17 और 18 अप्रैल को जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस क्षेत्र में एक सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि हस्तसाल पुनर्वासित कॉलोनी में कुल 30 ऐसे ढाबे थे, जिनके पास व्यापार चलाने के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य लाइसेंस नहीं था।

सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख, कहा- पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करेगी सरकार

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा दुख व्यक्त किया है। रविवार तड़के हुए इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्चे समेत 9 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित परिवारों को दिल्ली सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा कि विवेक विहार की एक इमारत में आग लगने की घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में 9 लोगों की असामयिक मृत्यु से मन बेहद व्यथित है। घायलों का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है और मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। उन्होंने आगे कहा कि इस कठिन समय में दिल्ली सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और ईश्वर उन्हें यह भारी दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वह स्थिति की लगातार निगरानी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी तत्परता के साथ बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। हादसे के वक्त स्थानीय विधायक और निगम पार्षद भी मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी विधायक संजय गोयल, पार्षद पंकज लूथरा और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी घटनास्थल का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया।

दिल्ली मेट्रो मेगा विस्तार -7 कॉरिडोर और 65 नए स्टेशन बनेंगे, आउटर दिल्ली में मजबूत होगी कनेक्टिविटी

नई दिल्ली। राजधानी में मेट्रो नेटवर्क को और व्यापक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने सात नए मेट्रो कॉरिडोर विकसित करने की योजना तैयार की है। इस विस्तार के तहत करीब 97 किलोमीटर लंबा नेटवर्क बिछाया जाएगा और 65 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि प्रस्तावित 'फेज-5बी' प्रोजेक्ट पर करीब ?48,000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसका मकसद उन इलाकों को मेट्रो से जोड़ना है, जो अब तक नेटवर्क से बाहर हैं या जहां कनेक्टिविटी सीमित है। इस योजना में नरेला, नजफगढ़, खेड़ा कलां और मीठापुर जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। नए रूट इन इलाकों को सीधे सेंट्रल और साउथ दिल्ली से जोड़ेंगे, जिससे रोजाना आने-जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने सात में से चार कॉरिडोर को प्राथमिकता श्रेणी में रखा है। इन पर काम तेज गति से करने की योजना है ताकि इन्हें 2029 से पहले चालू किया जा सके। परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है और अब अंतिम मंजूरी का इंतजार है।

महंगाई....

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 993 रुपए की भारी-भरकम वृद्धि और आने वाले दिनों में पैट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से सभी क्षेत्रों में चिंताएं गहरी हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3000 से ऊपर हो गई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से पैदा हुए गम्भीर संकट के बावजूद दो महीने से पैट्रोल और तेल की कीमतों को थाम कर रखा हुआ है और सरकार इनकी उपलब्धता के वैकल्पिक रास्ते निकालने में जी-जान से जुटी हुई है। आम जनता पर महंगाई का बोझ कम से कम पड़े इसलिए घरेलू रसोई गैस की कीमत नहीं बढ़ाई गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के चलते वैश्विक स्तर पर जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं उससे रोजाना इस्तेमाल की जरूरत की वस्तुओं की सप्लाई बाधित होने से महंगाई का झटका लगना तय था। अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के लिए विमानों के ईंधन और थोक डीजल के मूल्यों में भी बढ़ोतरी कर दी गई। पश्चिम एशिया से एलपीजी सप्लाई बाधित होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। रिफाइनिंग कम्पनियों द्वारा एलपीजी उत्पादन बढ़ाए जाने और अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि से कार्गो प्राप्त किए जाने के बावजूद घरेलू स्तर पर एलपीजी की बिक्री पर विपणन कम्पनियों का घाटा अभी भी ऊंचा बना हुआ है। यदि मौजूदा घाटे का स्तर पूरे वित्त वर्ष तक बना रहा तो सरकारी तेल विपणन कम्पनियों को एलपीजी की बिक्री पर लगभग 80 हजार करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत 125 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर जा रही है। पैट्रोल और डीजल की बिक्री पर क्रमशः14 रुपए प्रति लीटर और 18 रुपए प्रति लीटर नुकसान होने का अनुमान है। उर्वरक क्षेत्र भी सल्फर और अमोनिया की कीमतों में वृद्धि से महत्वपूर्ण लागत दबाव का सामना कर रहा है। कमर्शियल गैस की कीमतों में भारी-भरकम बढ़ोतरी से रेस्तरां, ढाबों, खान-पान सेवाओं, बेकरियों और क्लाउड किचनों में परेशानी की लहर दौड़ गई है। सबसे बड़ा संकट तो स्ट्रीट फूड का धंधा करने वालों पर आ खड़ा हुआ है। स्ट्रीट फूड का नेटवर्क इतना बड़ा है जो हर दिन करोड़ों भारतीयों को भोजन उपलब्ध कराता है। छोटे-छोटे व्यवसाय करने वालों के पास लम्बे समय तक लागत बढ़ने के झटकों को झेलने के लिए संसाधन नहीं होते। गैस संकट के चलते रेस्तरां मालिक पहले ही इधर-उधर भटक रहे हैं। कई रेस्तरां और ढाबे वालों ने अपना काम अस्थाई रूप से बंद कर दिया है और सड़क किनारे रेहड़ियां लगाने वालों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। केन्द्र सरकार गैस की सप्लाई निर्बाध जारी रखने की हर सम्भव कोशिश कर रही है लेकिन उपभोक्ताओं के लिए हर मद 5 या 10 रुपए महंगी हो चुकी है। भारत में मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग महंगाई के दौर में अपनी मांग घटा देते हैं। इसका प्रभाव सब्जी व्यापारी, डेयरी विक्रेता और अन्य खानपान की वस्तुओं पर पड़ रहा है। छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए तो उनमें काम करने वाले लोगों का रोजगार भी प्रभावित होगा। पैट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें तो कुछ देशों ने खुदरा कीमतों में वृद्धि कर दी है। केन्द्र सरकार ने तेल कम्पनियों की रक्षा करने के लिए पैट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। यदि अमेरिका और ईरान युद्ध फिर भड़क उठता है तो कीमतें बढ़ना निश्चित हो ही जाएगा। एशिया के कुछ देशों और अन्य कई देशों में कर ढांचा इस तरह का बनाया गया है कि जब भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो वहां तेल पर उत्पाद शुल्क कीमतों के अनुपात में कम कर दिया जाता है। जब कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया जाता है। इससे आम उपभोक्ता पर कीमतों का दबाव नहीं आता। वर्तमान परिस्थितियों में अब यह जरूरी हो गया है कि उत्पाद शुल्क नीतियों को अधिक निश्चित और पूर्वानुमान योग्य बनाया जाए। भारत में अभी 60 दिन का रिजर्व पैट्रोल है। शुरुआत में उम्मीद थी कि युद्ध जल्दी खत्म होगा और तेल कम्पनियां अपने पुराने मुनाफे से स्थितियां सम्भाल लेंगी लेकिन अब जबकि संकट लम्बा खिंचता दिख रहा है तो पैट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि का तूफान आ सकता है। सरकार पहले से ही एलपीजी और उर्वरक सब्सिडी का बोझ उठा रही है। ऐसे में पैट्रोल-डीजल पर घाटा सहना सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ा सकता है। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट में कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि केवल तेल और गैस के भंडारण तक ही सरकारें सीमित न रहें, बल्कि प्रमुख आवश्यक कच्चे माल के भंडार भी बनाए जाएं। संकट काल में हमेशा यह देखा गया है कि कई देश महत्वपूर्ण कच्चे माल और वस्तुओं के उत्पादन में अपने प्रभुत्व को हथियार बना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सप्लाई चेन के प्रभावित होने से आयातित यूरिया की कीमत 950 डॉलर प्रतिटन हो गई है, जो पिछले वर्ष अप्रैल में 390 डॉलर प्रति टन थी। आयातित अमोनिया की कीमत 775 डॉलर प्रतिटन के स्तर पर पहुंच गई है, जो पिछले साल 365 डॉलर प्रति टन थी। चिप की कीमत में पिछले साल की तुलना में 560 गुणा बढ़ोतरी हो चुकी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक युद्ध से पहले वर्ष 2026 में वैश्विक विकास की दर 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था जिसे मार्च में 3.1 प्रतिशत कर दिया गया। अब यह विकास दर 2.5 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। वहीं वैश्विक विकास दर 5.4-6.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत इससे अछूता नहीं रह सकता है। हालांकि वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश की घरेलू अर्थव्यवस्था के मानक मजबूत दिख रहे हैं। इस कारण देश की विकास दर मजबूत बनी रहेगी। फिलहाल मुद्रास्फीति की कहानी गहरी हो चुकी है और उपभोक्ताओं का व्यवहार तेजी से बदल रहा है। वैसे तो भारत बड़े से बड़े संकट को झेल चुका है। सीधे-सीधे अब चौतरफा महंगाई का असर आम लोगों की थाली और हर चीज पर पड़ रहा है। देश की बड़ी आबादी रोजी और रोजगार से जूझ रही है जो अपने आप में बड़ी चुनौती है।

लोकतंत्र की पंचवर्षीय फिटनेस परीक्षा

पांच राज्यों में चुनाव सम्पन्न हो गए हैं। लोकतंत्र ने फिर से अपनी पंच वर्षीय फिटनेस परीक्षा दे दी है। अब वोट ईवीएम में विश्राम कर रहे हैं—जैसे किसी सरकारी दफ्तर में फाइलें, जिन्हें चार मई तक जब मर्जी बदला जा सकता है। और इन ईवीएम का भविष्य चार मई को ही खुलेगा। तब तक जनता, दल और चैनल—तीनों एग्जिट पोल के सहारे जीवन यापन कर रहे हैं। असली परिणाम आने तक अनुमान ही हमारा राष्ट्रीय मनोरंजन है। और जिन्हें इसमें मनोरंजन नहीं मिल रहा हो, उनके लिए आईपीएल तो है ही। देश में चुनाव हुए, होने भी चाहिए। राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़े, लड़ने भी चाहिए। परिणाम आएंगे, आने भी चाहिए। आखिर लोकतंत्र का यही सौंदर्य है कि हर पांच साल में जनता को यह अवसर दिया जाता है कि वह तय करे कि अगले पांच साल तक उसकी कौन अनसुनी करेगा और कौन उसके कष्टों का कारण बनेगा। इस बार पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव हुए। वैसे वहां चुनाव हर पांच साल में होते हैं, और तब तक होते रहेंगे जब तक कि लोकतंत्र को किसी और प्रयोगशाला में तब्दील न कर दिया जाए। बंगाल के चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, और सरकार जी के लिए तो ये इतने नाक का सवाल होते हैं कि मानो देश की जीडीपी, विदेश नीति और मौसम, सबका भविष्य वहीं से तय होना हो। 2016 में भी उन्होंने पूरा जोर लगाया था, 2021 में भी। हर बार उनका चुनावी रथ बंगाल की सीमा तक पहुंचता है, खूब धूल उड़ाता है, और फिर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। इस बार भी जोर कम नहीं लगाया गया। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रशासनिक, अर्ध-प्रशासनिक और परा-प्रशासनिक प्रयास किए गए। पहले एसआईआर करवाई गई। लाखों वोटों को लोकतंत्र से जबरन रिटायर कर दिया गया। बिहार मॉडल जब इतना सफल रहा तो उसका फ्रेंचाइजी विस्तार बंगाल तक तो होना ही था। आखिर सफल प्रयोगों का विस्तार ही तो सुशासन की पहचान है। फिर अफसरों का स्थानांतरण हुआ। चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए वहां अफसर लगाए गए जो निष्पक्षता को इतनी कुशलता से निभा सकें कि वह सीधे सत्ता पक्ष के पक्ष में जा गिरे। यूपी, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में ऐसे प्रतिभाशाली अफसरों की कोई कमी नहीं है। वे लोकतंत्र के ऐसे कारीगर हैं जो मतपेटी से मनचाहा परिणाम निकालने की कला में निपुण होते हैं।

बंगाल, केरल और तमिलनाडु के अफसर भी कम योग्य नहीं, पर उनकी योग्यता का सम्मान इसी में समझा जाता है कि चुनाव के समय उन्हें सम्मानपूर्वक किनारे कर दिया जाए। वैसे चुनाव आयोग भी पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभा रहा है। अपने नियोक्ता का वफादार बना हुआ है। पर सरकार जी का स्वभाव थोड़ा आत्मनिर्भरता का है। वे चाहते हैं कि जीतें तो अपनी मेहनत से जीतें, और हारें तो इतनी मेहनत के बाद हारें कि शिकायत करने का मौका न रहे। इसी आत्मनिर्भरता के कारण वे इस बार बंगाल में लगभग पंद्रह दिन डेरा डाले रहे। दुनिया में कहीं युद्ध हो, देश में गैस संकट हो, लोग सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े हों, ये सब स्थानीय समस्याएं हैं। राष्ट्रीय समस्या तो यह थी कि बंगाल में चुनाव कैसे जीता जायेगा। वैसे देशहित में एक सुझाव है। सरकार जी की पार्टी को चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए। इससे सरकार जी को देश चलाने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। अभी तो साल के तीन-चार महीने चुनावों में ही निकल जाते हैं। बाकी समय अगले चुनाव की तैयारी में। ऐसे में शासन कब हो, कैसे हो, यह बस एक अकादमिक प्रश्न बनकर रह जाता है। और जहां तक राज्यों में अपनी सरकार बनाने का प्रश्न है, उसके लिए चुनाव ही एकमात्र उपाय तो नहीं है। हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, आयकर विभाग है। लोकतंत्र के ये आधुनिक औजार किसी भी चुनाव परिणाम को अधिक व्यावहारिक बना सकते हैं। और फिर विधायक खरीदने के लिए संसाधनों की भी कोई कमी तो नहीं है। लोकतंत्र में पूंजी का भी अपना योगदान होता ही है। सरकार जी यह कला पहले भी प्रदर्शित कर चुके हैं और हाल में भी। पंजाब से राज्यसभा सदस्य खरीदने की घटना इसका ताजा उदाहरण है। जहां आपके अपने विधायक उंगलियों पर गिने जा सकें, उस राज्य से राज्यसभा सदस्य हो, साधारण राजनीतिक उपलब्धि नहीं, यह संसदीय रसायनशास्त्र है। जहां आलू डालो और सोना निकल आए। पैसा डालो और राज्यसभा सांसद मिल जाए। आखिर जब मिठाई सीधे बाजार में उपलब्ध हो, तो पहले दूध खरीदना, उसे उबालना, खोया बनाना, चीनी मिलाना, कड़ाही चलाना—इतनी मेहनत कौन करे और फिर भी गारंटी नहीं कि मिठाई ठीक बने। इससे अच्छा है कि सीधे तैयार मिठाई खरीद ली जाए। न खराब बनने का डर, न मेहनत की झंझट। जितनी चाहिए, उतनी खरीदिए। समय भी बचेगा, धन भी। और जो तन-मन-धन बचेगा, उसे देश की उन्नति में लगाया जा सकता है। मतलब अगले चुनाव में लगाया जा सकता है।

सम्पादकीय...

समाज व राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने हेतु प्रेरित कर रहीं संत रविदास जी की शिक्षाएं

युवा भारत जो सशक्त हो रहा है, उसकी जड़ें भारतीय संतों की परंपरा में हैं। वक्त-वक्त पर आपस में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना लोगों को संतों ने सिखाया। संत रविदास जी इसके अभिन्न अंग हैं। उनके काम और उनके काम के परिणामों को देखकर ही समकालीन संतों ने उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी थी। संत रविदास जी एक भारतीय रहस्यवादी, कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने भक्ति गीतों, कविताओं और आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संत रविदास जी का जुनून सत्य की खोज था। उनका कहना था कि ज्येष्ठ-कनिष्ठ का विचार सरासर गलत है। सत्य, करुणा, आंतरिक पवित्रता और निरंतर कड़ी मेहनत रविदास जी का उपदेश था। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में माघ पूर्णिमा संवत 1433 या 15वीं शताब्दी को माता कलसा देवी और पिता संतोख दास के घर हुआ। उन्होंने अपने जूते बनाने के पैतृक व्यवसाय को जारी रखा और इसे ही ईश्वर सेवा माना लेकिन जल्द ही वे अपना अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय तपस्वियों, साधुओं और सूफी-संतों के साथ बिताया। रविदास का विवाह कम उम्र में लोना देवी से हुआ था। उनके पुत्र विजय दास का जन्म हुआ। भक्ति आंदोलन के कई कवियों की सबसे पुरानी जीवनियों में से एक, अनंतदास परचई, रविदास के जन्म का वर्णन करती है। भक्तिमाल जैसे मध्यकालीन साहित्य के अनुसार, रविदास जी भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे। उन्हें आमतौर पर कबीर का समकालीन माना जाता है। फिर भी, प्राचीन साहित्य रत्नावली का दावा है कि गुरु रविदास ने रामानंद से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की और वे रामानंदी संप्रदाय से संबंधित थे। उन्होंने व्यापक यात्रा की और गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हिमालय में स्थित हिंदू तीर्थ स्थलों का दर्शन किया। उन्होंने सर्वोच्च सत्ता के सगुण (विशेषताओं सहित, चित्रमय) रूपों का त्याग कर निर्गुण (अमूर्त, गुणों रहित) रूप पर ध्यान केंद्रित किया। उनके क्षेत्रीय भाषाओं में रचित रचनात्मक भजनों से प्रेरित होकर, सभी पृष्ठभूमि के लोग उनसे शिक्षा और परामर्श लेने आते थे। आर.एस.एस. के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी के शब्दों में, ''एक साधारण परिवार से आने वाले संत श्री रविदास जी की महानता को काशी के विद्वानों सहित समाज के सभी वर्गों ने उनकी सर्वोच्च भक्ति, सेवाभाव और समाज के प्रति शुद्ध प्रेम के कारण स्वीकार किया। काशी के राजा, झाली रानी और मीराबाई जैसे राजपरिवार के सदस्य भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। संत रविदास जी महाराज द्वारा रचित लगभग 41 शब्द (भजन) गुरु ग्रंथ साहिब में 'बानी भगतन की' के अंतर्गत विभिन्न रागों (जैसे राग आसा, राग धनासरी, आदि) में सम्मिलित हैं। जाति-पाति का विरोध और ईश्वर की एकता जैसी उनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब के सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

मां की ममता मौत के बाद भी जीती

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहां एडवेंचर टूरिस गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। बोटिंग तथा समुद्री गतिविधियों के प्रति लोगों का क्रेज भी बढ़ा है लिहाजा, ऐसी गतिविधियों की लोकप्रियता नदियों, समुद्र वाले क्षेत्रों में बहुत बढ़ गई है। ये बहुत आकर्षक व मनमोहक हैं लेकिन अगर सुरक्षा नहीं तो समझो जान आफत में चली जाती है। दो दिन पहले जबलपुर में बरगी डैम के पानी में हुए करूण हादसे ने सचमुच हिलाकर रख दिया है। कुल 9 लोग डूबकर मर गए लेकिन जिस मां व उसके साल भर के बेटे की मौत का भयावह मंजर सोशल मीडिया पर उभरा जिसने पूरी दुनिया की मानवता को झकझोर कर रख दिया है। एक मां के सीने से उसका मासूम बेटा चिपका पड़ा है। दोनों के शव जब डैम के गहरे पानी से निकाले गए तो भी वे अलग नहीं हो रहे थे। मां की ममता मौत के बाद भी जीत गई। लाइफ जैकेट पहने मां और उसके सीने से चिपके बेटे की यह दर्दनाक तस्वीर देखकर हर किसी की रुह कांप गई। अथाह पानी के बीच वह मां अपने बेटे को बचाने के लिए सीने से लगाकर आखिरी सांस तक लड़ती रही। यह मां और बेटा दिल्ली से गए उस परिवार के सदस्य थे जिसमें इन दोनों को तो काल ने निगल लिया लेकिन पानी की बेरहम लहरों से बचे पिता और बेटी अब जिंदगी भर इस ट्रेजिडी को कभी भुला नहीं पायेंगे। मां-बेटे और साथ ही अन्य लोगों की मौत एक सवालिया निशान लगा रही है। आखिरकार ये लाइफ जैकेट कितनी सेफ है। क्या लाइफ जैकेट सुरक्षा की गारंटी है। इसका जवाब कौन देगा मौसम के बदलाव या चेतावनी को लेकर क्रूज में सवार चालक दल तथा निगरानी केंद्र के स्टाफ में तालमेल नहीं था तो इस सवाल का भी जवाब कौन देगा जबलपुर में हुई क्रूज दुर्घटना ने एक बार फिर भारत में जल-सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से सामने ला दिया है। ऐसी घटनाएं यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारे देश में पानी से जुड़ी गतिविधियों—जैसे बोटिंग, क्रूज यात्रा या नदी-झील पर्यटन के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है या नहीं। साथ ही, जब हम सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों को देखते हैं, तो वहां की सुव्यवस्थित और सुरक्षित जल-पर्यटन प्रणाली हमें एक तुलना करने के लिए प्रेरित करती है। जबलपुर में हुई दुर्घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अक्सर देखा जाता है कि नावों में क्षमता से अधिक लोग बैठा लिए जाते हैं, लाइफ

जैकेट्स की कमी होती है और चालक (ऑपरेटर) को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। कई बार सुरक्षा नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। यह लापरवाही जानलेवा साबित होती है। मेरा मानना है कि जबलपुर जैसी घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। भारत में जल पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार, प्रशासन और आम जनता तीनों को मिलकर काम करना होगा। सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों से हमें सीख लेनी चाहिए कि कैसे सख्त नियम, जागरूकता और तकनीक के जरिए हादसों को रोका जा सकता है।

आज की तारीख में अगर हम सही कदम उठाएं, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत में भी लोग पानी से जुड़ी गतिविधियों का आनंद बिना किसी डर के ले सकेंगे। सुरक्षा को प्राथमिकता देना ही सबसे बड़ा समाधान है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग, गोवा में बोटिंग और वॉटर स्पोर्ट्स और दिल्ली के आसपास झीलों व नदियों में बोटिंग, ये सभी लोगों को आकर्षित करते हैं लेकिन इनके साथ सुरक्षा के गंभीर सवाल भी जुड़े हुए हैं। हर साल कई हादसे सामने आते हैं, जिनमें लापरवाही, खराब व्यवस्था और जागरूकता की कमी मुख्य कारण होते हैं। ऐसे हादसों की खबरें अक्सर सुर्खियां बन कर उभरती रहती हैं। मौसम की खराब स्थिति हो या जैकेट न होना या फिर इनके रखरखाव में कमी, किसी को भी दोष दें लेकिन यह सच है कि हमारे यहां हादसों के बाद जांच की घोषणाओं के साथ ही सब सामान्य हो जाता है। गोवा समुद्री पर्यटन का केंद्र है। यहां पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड और क्रूज जैसी गतिविधियां बहुत लोकप्रिय हैं। सरकार और पर्यटन विभाग ने सुरक्षा के लिए कई नियम बनाए हैं, जैसे लाइफ जैकेट पहनना और लाइसेंसधारी ऑपरेटर का होना लेकिन नावों में क्षमता से अधिक लोग बैठा लिए जाते हैं और कहीं शराब पीकर वॉटर स्पोर्ट्स करने की घटनाएं होती हैं। लाइफगार्ड की संख्या हर जगह पर्याप्त नहीं होती, बड़ी बात यह है कि पानी या समुद्र का स्वभाव अनिश्चित होता है। अचानक लहरें तेज हो सकती हैं या मौसम बदल सकता है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा बन सकती है। जबलपुर हादसा भी इसी कारण हुआ बताया जा रहा है। कई रिपोर्टों में हादसों को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं जिनमें लाइफ जैकेट का उपयोग तथा नावों की खराब स्थिति पर चर्चा हुई। कई नावों या क्रूज में कोई प्रशिक्षित गाइड या बचाव दल मौजूद नहीं। ऐसी घटनाओं में अक्सर लोग डूब जाते हैं क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता और तुरंत मदद भी नहीं मिल पाती। जबलपुर हादसा भी कुछ ऐसी ही खामियां उजागर कर रहा है। सच तो यह है कि भारत में राफ्टिंग और बोटिंग का अनुभव रोमांचक

बोटिंग तथा समुद्री गतिविधियों के प्रति लोगों का क्रेज भी बढ़ा है लिहाजा, ऐसी गतिविधियों की लोकप्रियता नदियों, समुद्र वाले क्षेत्रों में बहुत बढ़ गई है। ये बहुत आकर्षक व मनमोहक हैं लेकिन अगर सुरक्षा नहीं तो समझो जान आफत में चली जाती है। दो दिन पहले जबलपुर में बरगी डैम के पानी में हुए करूण हादसे ने सचमुच हिलाकर रख दिया है। कुल 9 लोग डूबकर मर गए लेकिन जिस मां व उसके साल भर के बेटे की मौत का भयावह मंजर सोशल मीडिया पर उभरा जिसने पूरी दुनिया की मानवता को झकझोर कर रख दिया है। एक मां के सीने से उसका मासूम बेटा चिपका पड़ा है। दोनों के शव जब डैम के गहरे पानी से निकाले गए तो भी वे अलग नहीं हो रहे थे। मां की ममता मौत के बाद भी जीत गई। लाइफ जैकेट पहने मां और उसके सीने से चिपके बेटे की यह दर्दनाक तस्वीर देखकर हर किसी की रुह कांप गई। अथाह पानी के बीच वह मां अपने बेटे को बचाने के लिए सीने से लगाकर आखिरी सांस तक लड़ती रही। यह मां और बेटा दिल्ली से गए उस परिवार के सदस्य थे जिसमें इन दोनों को तो काल ने निगल लिया लेकिन पानी की बेरहम लहरों से बचे पिता और बेटी अब जिंदगी भर इस ट्रेजिडी को कभी भुला नहीं पायेंगे। मां-बेटे और साथ ही अन्य लोगों की मौत एक सवालिया निशान लगा रही है।

जरूर है लेकिन इसमें जोखिम भी शामिल है। ऋषिकेश, गोवा और दिल्ली जैसे स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है लेकिन उसका सही पालन जरूरी है। हर साल होने वाले हादसे हमें यह याद दिलाते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। अगर सरकार सख्ती से नियम लागू करे और लोग खुद भी जिम्मेदारी दिखाएं तो इन हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है। रोमांच का आनंद तभी सही है, जब वह सुरक्षित हो।

एक तरफ न्याय और दूसरी तरफ अन्याय

माना कि हरेक राष्ट्रप्रेमी गोली मारने लगेगा, तब भी और बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे भावना राष्ट्रप्रेम की है, न कि मुसलमानों या और किसी के भी प्रति नफरत की। रही बात ''सालों को'' की तो साला शब्द के प्रयोग में जरूर नफरत की आशंका हो सकती है क्योंकि इस शब्द का प्रयोग कई बार गाली की तरह भी किया जाता है। लेकिन, यह एक प्यारे रिश्ते का नाम भी तो है। यह भी हो सकता है कि नारे में साला शब्द का प्रयोग इस प्यार भरे अर्थ में ही किया गया हो। अदालत संदेह का लाभ देकर, ''गोली मारो सालों को'' का नारा लगाने वालों को, नफरती बोलों के आरोपों से बरी करती है। मोदी जी-शाह जी की पार्टी को चुनाव में, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, हरेक सीजन में अपने इस नारे का प्रयोग करने का अधिकार है।

इसे कहते हैं न्याय! अदालत ने क्या दूध का दूध और पानी का पानी किया है। दूध अलग और पानी अलग। मजाल है, जो दूध में पानी का कतरा मिलने दिया हो। और पानी में दूध का एक छींटा रहने देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक तरफ न्याय और दूसरी तरफ अन्याय। और दोनों के बीच कोई बारीक सी रेखा नहीं बल्कि समझिए कि चीन की दीवार की टक्कर की दीवार खींच दी है कि रत्तीभर मिलावट का कोई चांस ही नहीं है। अदालत ने पहले नफरती बोलों के दूध को छानकर अलग किया। यह तो बहुत ही खतरनाक चीज है। इसको अनदेखा करना देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। कानून में इससे निपटने के लिए काफी उपाय हैं। पता नहीं क्यों इससे निपटने में अक्सर ढील देखने को मिलती है, वगैरह, वगैरह। फिर एक झटके में पानी को इस दूध से अलग कर दिया--''गोली मारो सालों को'' का नारा लगाने में तो कोई नफरती बोल है ही नहीं। एक सिंपल नारा है और वह भी चुनाव के टैम का नारा। यह कैसी विडंबना है कि एक तरफ तो सेकुलर वाले चुनावी नारों में नफरती बोल खोज रहे हैं और दूसरी ओर इसकी शिकायतें करते हैं कि मोदी जी-शाह जी के राज में, नफरती बोलों की बाढ़ आयी हुई है। बाढ़ आयी हुई है तो बाढ़ में से कहीं से भी नफरती बोल का ढेला भर लाते, मोदी जी के दो हीरों--अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा--पर ही निशाना लगाने की कोशिश क्यों? न्यायाधीशों ने तो पहली नजर में ही पहचान लिया कि यह पॉलिटिक्स का मामला है। पॉलिटिक्स का भी क्या, बस मोदी जी के विरोध का मामला है। मोदी जी के विरोधियों को विरोध करने के लिए और कुछ नहीं मिला तो मोदी जी के चहेते युवा सांसदों पर नफरती बोली बोलने का इल्जाम लगा दिया। और इल्जाम भी किस ने लगाया एक विपक्षी नेता ने। और विपक्षी भी ऐसी-वैसी नहीं, कम्युनिस्ट नेता ने। अब कम्युनिस्टों का तो नफरत सूंघने का स्पेशलाइजेशन ही माना जाता है। सात पर्दों में छुपी नफरत भी सूंघ निकालते हैं। और उस पर तुर्रा ये है कि ये खुदाई खिदमतगार हैं। चुनाव दिल्ली में हो रहा था। ठाकुर जी और वर्मा जी दिल्ली के चुनाव में ''गोली मारो...को'' का आह्वान कर रहे थे। दिल्ली में चुनाव में उनकी पार्टी का मुकाबला, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से था। पर शिकायत हुई लाल झंडे वाली पार्टी की नेता को, जिनकी पार्टी चुनाव में कहीं दूर-दूर थी ही नहीं। सोचने की बात है, अगर ''गोली मारो...को'' में नफरत के बोल होते, तो क्या केजरीवाल की पार्टी को नहीं सुनाई देते, जिसने उस बार तो चुनाव जीता भी था। हैरानी की बात नहीं है कि अदालत ने पहली नजर में ही पकड़ लिया कि यह नफरती बोल वगैरह के खिलाफ किसी न्याय-व्याय का नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स का मामला है। सच्ची बात तो यह है कि सबसे ऊंची अदालत ने तो अब पकड़ा, बाकी अदालतें भी शुरू से ही इस सच्चाई को न सिर्फ जाने बैठी थीं बल्कि पकड़ के भी बैठी थीं। और अदालतें ही क्यों अमित शाह जी वाली दिल्ली पुलिस भी। तभी तो दिल्ली पुलिस को कभी ''गोली मारो...को'' में कोई नफरती बोल नहीं सुनाई दिया। वैसे भी दिल्ली पुलिस पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है और जो ऊपर से कहा जाता है, उसे ही ठीक से सुन-समझ लें तो ही बहुत है। इधर-उधर के बोल भी सुनने के चक्कर में पड़ेंगे, तब तो शायद कुछ भी सुनने लायक नहीं रह जाएंगे। अगर इधर-उधर के बोल सुनने लगते तो क्या उन्हें अमित शाह का वोटिंग मशीन के बटन से शाहीन बाग में करंट लगाने वाला डायलॉग भी नहीं सुनना पड़ता! बॉस के नफरती बोल...वह तो कुफ्र हो जाता। उन्होंने कुछ नहीं सुना। और जब शाह जी की पुलिस को कोई नफरती बोल नहीं सुनाई दिये, तो निचली अदालत को कैसे सुनाई देते अदालतों पर काम का बोझ कम है क्या जब निचली अदालत ने नफरती बोल नहीं सुने, तो हाई कोर्ट कैसे सुनती दिल्ली के ही जस्टिस मुरलीधरन की तरह, रातों-रात जज साहब को दंडात्मक तबादला कराना था क्या और आखिरकार, सबसे ऊंची अदालत को भी ''गोली मारो...को'' में कोई नफरती बोल नहीं सुनाई दिए। केस क्लोज्ड, याचिका खारिज! अब प्लीज ये मत कहने लगिएगा कि अदालत के ही कान बंद थे, इसलिए उसे नफरती बोल सुनाई नहीं दिए। इसमें कान का तो काम ही नहीं था। सारा मामला तो यूं ही एकदम साफ था। अदालत की क्लीन चिट तो बनती थी--''देश के गद्दारों को, गोली मारो...को'' के लिए! दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के नौजवान नेताओं का नारा था, उसके लिए क्लीन चिट तो यों भी बनती ही थी। नारा है, आगे भी देश को सेवा के लिए काम आएगा, चुनाव में भी और चुनाव से पहले भी तथा बाद में भी। वैसे भी गोली मारो के आह्वान में नफरत वाली तो कोई बात है ही नहीं। बेशक, इस आह्वान को कोई हिंसक कह सकता है, लेकिन था तो सिर्फ आह्वान ही। गोली किसी को मारी गयी क्या कहां तो भारतीय ज्ञान परंपरा की नयी पढ़ाई में यह पढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं कि गोडसे ने गांधी को जो तीन गोलियां मारी थीं, वो भी नफरत की वजह से नहीं बल्कि राष्ट्र से प्रेम की वजह से मारी थीं; और कहां गोली मारने की सिर्फ पुकार को जबरन नफरत से जोड़ा जा रहा है, जबकि गोली एक भी नहीं चली थी, शाहीन बाग के सिवा। फिर यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी के पार्टी के युवा नेताओं ने गोली किसी मारने की पुकार उठायी थी। देश के गद्दारों को! देश के गद्दारों को गोली मारने का भला नफरत से क्या लेना यह तो राष्ट्रप्रेम का काम है! माना कि हरेक राष्ट्रप्रेमी गोली मारने लगेगा, तब भी और बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे भावना राष्ट्रप्रेम की है, न कि मुसलमानों या और किसी के भी प्रति नफरत की। रही बात ''सालों को'' की तो साला शब्द के प्रयोग में जरूर नफरत की आशंका हो सकती है क्योंकि इस शब्द का प्रयोग कई बार गाली की तरह भी किया जाता है। लेकिन, यह एक प्यारे रिश्ते का नाम भी तो है। यह भी हो सकता है कि नारे में साला शब्द का प्रयोग इस प्यार भरे अर्थ में ही किया गया हो। अदालत संदेह का लाभ देकर, ''गोली मारो सालों को'' का नारा लगाने वालों को, नफरती बोलों के आरोपों से बरी करती है। मोदी जी-शाह जी की पार्टी को चुनाव में, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद,

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, ... दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2018/...)

गीडा में पत्नी-बच्चों पर फायरिंग का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

गोरखपुर। थाना गीडा क्षेत्र में घरेलू विवाद ने खतरनाक रूप ले लिया, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चों पर फायरिंग कर जान लेने का प्रयास किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक, ग्राम जैतपुर निवासी अमित चन्द्र जायसवाल आए दिन शराब के नशे में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था। घटना वाले दिन भी वह नशे में था और गाली-गलौज करते हुए अवैध तमंचा निकालकर पत्नी व बच्चों को धमकाने लगा। इसी दौरान उसने फायरिंग कर दी, हालांकि गोली महिला के बगल से निकल गई और वह बाल-बाल बच गई। पीड़िता की शिकायत पर थाना गीडा में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

अपराध निरोधक समिति की बैठक सम्पन्न

समाज से घृणा समाप्त करना व सामाजिक सरोकार मुख्य उद्देश्य

फरेन्दा महराजगंज ।

उत्तर प्रदेशीय अपराध निरोधक समिति के चेयरमैन कमलेश श्रीवास्तव के निर्देश पर जिला अपराध निरोधक समिति की बैठक चन्द्रा पब्लिक स्कूल मे जिला उपाध्यक्ष सुधेश मोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षता मे हुई बैठक का संचालन जिला सचिव श्रीनाथ दूबे ने किया।
बैठक को सम्बोधित करते हुये उपाध्यक्ष सुधेश मोहन श्रीवास्तव ने कहा की समिति का उद्देश्य अपराधियों से नही अपराध से घृणा करने की है समाज मे सरोकार कैसे बने-बढे इसपर काम करना होगा तथा अपराधिओं को भी सुधरने का मौका देना होगा जिससे एक अछे समाज की संरचना हो सके। बैठक का संचालन करते हुये जिला सचिव श्रीनाथ दूबे ने कहा की प्रदेश के निर्देश पर सेवा पथ पुस्तिका का प्रकाशन होने जा रहा जिसमे पूरे प्रदेश की भागीदारी होगी समिति का मुख्य उद्देश्य सभी पर्व नजर रखने व समाज विरोधी तत्वों के बारे मे पुलिस-और शासन को अवगत कराना है इसके आलावा मन्दिरो व अन्य सार्वजनिक स्थान पर शांति व्यवस्था व्यवस्था बनाये रखना है उन्होंने नयी सदस्या बनाने तथा पुरानी सदस्ता के नवीनी करण की बात भी कही। बैठक मे मुख्य रुप से कृष्ण कुमार पाण्डेय,पूर्व चेयरमैन विनोद गुप्ता,विनय श्रीवास्तव, विष्णु देव त्रिपाठी,रमेश चंद श्रीवास्तव, मनोज जायसवाल, हरिनारायण यादव, राम शरण गुप्ता व प्रमोद कुमार सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे।

आमी समेत नदियों और जलस्त्रोतों को बचाने की उठी आवाज, जन आयोग गठन का निर्णय

पानी की बात, आपके साथ विषय पर आयोजित सम्मेलन में जल प्रदूषण से बढ़ती गंभीर समस्याओं पर जताई गई चिंता

गोरखपुर। पूर्वांचल में बढ़ते जल एवं नदी प्रदूषण, अतिक्रमण और पर्यावरण संकट को लेकर प्रेस क्लब सभागार में पानी की बात, आपके साथ विषय पर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें आमी सहित क्षेत्र की नदियों, तालाबों और जलस्त्रोतों को बचाने के लिए जनआंदोलन चलाने का संकल्प लिया गया। साथ ही नदियों के किनारे जल पंचायतों के आयोजन की घोषणा की गई। म्मेलन को संबोधित करते हुए आमी बचाओ मंच के अध्यक्ष एवं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय सिंह ने जल प्रदूषण से बढ़ती गंभीर समस्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बड़ा जल संकट खड़ा होगा। नदियों को बचाने के लिए जनसंघर्ष और कानूनी लड़ाई तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर शरद चन्द्र मिश्र एवं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक चौधरी ने सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आमी नदी को प्रदूषित करने वाले उद्योगों पर कठोर कार्रवाई, सीईटीपी की स्थापना, नदियों को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त कराने, फ्लड प्लेन व जलाशयों की भूमि पर विकास योजनाओं पर रोक, नदी प्रवाह में कृत्रिम बदलाव रोकने, नदी पर निर्भर लोगों के अधिकारों की गारंटी और कटान प्रभावितों के पुनर्वास की मांग की गई। इसके साथ ही नदियों के संरक्षण, स्वच्छ और निर्बाध प्रवाह तथा नदी पर निर्भर जनसमुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए जन आयोग गठन का निर्णय लिया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

वर्धान मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ, क्षेत्र को मिली आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल शुरू, 24 घंटे विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध

गोरखपुर।

शहर के स्वास्थ्य क्षेत्र में रविवार को एक नई उपलब्धि जुड़ गई, जब गोरखपुर-देवरिया रोड स्थित कुनराघाट (AIIMS थाना के सामने) में वर्धान मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अस्पताल के शुरू होने से क्षेत्रवासियों को अब आधुनिक और उचस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. धर्मेन्द्र सिंह (एमएलसी, भाजपा) रहे, जबकि सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने फीता काटकर अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आधुनिक चिकित्सा संस्थान क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आमजन को बेहतर व सुलभ इलाज उपलब्ध कराते हैं। उद्घाटन समारोह में डॉ. शिशिर राय (पीडियाट्रिशियन), डॉ. योति

कुशवाहा (गाइनकोलॉजिस्ट), डॉ. दिव्या राय (डर्मेटोलॉजिस्ट), डॉ. आई. कुशवाहा (रेडियोलॉजिस्ट) तथा जितेन्द्र चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने अस्पताल की सुविधाओं की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, यहां 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अस्पताल में प्रसूति एवं स्त्री रोग, शिशु रोग, त्वचा रोग, सामान्य चिकित्सा, आपातकालीन सेवाएं, पैथोलॉजी, डिजिटल एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही आईसीयू, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, स्वच्छ वार्ड और प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया गया तथा अस्पताल परिसर का भ्रमण कर आधुनिक उपकरणों और व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। स्थानीय लोगों ने अस्पताल के उद्घाटन पर खुशी जताते हुए कहा कि अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि उनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिल सके।

लाइब्रेरियन के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी, सांसद रमाशंकर राजभर की पहल पर राजभवन सख्त

सलेमपुर सांसद ने कुलाधिपति को पत्र लिखकर उठाया था मुद्दा; राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी ने प्रमुख सचिव को दिए निर्देश

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वर्षों से खाली पड़े हैं पद; शासन से मांगी गई कृत कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट

देवरिया। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में लाइब्रेरियन के रिक्त पदों पर भर्ती की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमाशंकर राजभर द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए राजभवन ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी (अपर मुख्य सचिव स्तर) डॉ. सुधीर एम. बोबडे ने इस संबंध में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को पत्र जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सांसद रमाशंकर राजभर ने बीते 16 मार्च 2026 को कुलाधिपति (राज्यपाल) को संबोधित एक पत्र प्रेषित किया था। पत्र में उन्होंने प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में पुस्तकालयाध्यक्षों की भारी कमी और इसके कारण छात्रों के पठन-पाठन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने मांग की थी कि रिक्त पदों पर तत्काल पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए ताकि पुस्तकालयों का संचालन सुचारु रूप से हो सके और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें। सांसद के इस पत्र पर राजभवन ने त्वरित प्रतिक्रिया दी है। राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रमुख सचिव को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही की जाए और इस संबंध में की गई प्रगति की रिपोर्ट सचिवालय को उपलब्ध कराई जाए। राजभवन की इस सक्रियता के बाद उच्च शिक्षा विभाग में खलबली मच गई है और अब रिक्त पदों का विवरण जुटाकर भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा रही है। क्षेत्रीय शिक्षाविदों और बेरोजगार युवाओं ने सांसद रमाशंकर राजभर की इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि लाइब्रेरियन के पदों पर वर्षों से भर्ती न होने के कारण कई संस्थानों में पुस्तकालय केवल नाममात्र के रह गए हैं। यदि यह भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होती है, तो प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अब सबकी नजरें शासन द्वारा की जाने वाली अगली कार्यवाही पर टिकी हैं।

एएसपी ने परखी रिक्रूट आरक्षियों की व्यवस्था, जवानों के साथ बैठकर किया भोजन

बैरक से लेकर मेस तक की सुविधाओं का लिया जायजा; गुणवत्तापूर्ण भोजन और साफ-सफाई पर दिया जोर

देवरिया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों की कार्यप्रणाली और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) आनंद कुमार पाण्डेय ने थाना बघौचघाट का औचक भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने थाने में प्रशिक्षण ले रहे नए जवानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। एएसपी ने न केवल बैरकों और मेस की साफ-सफाई देखी, बल्कि एक अभिभावक की भूमिका में रिक्रूट आरक्षियों के साथ बैठकर जमीन पर बैठकर भोजन भी किया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने मेस, पेयजल आपूर्ति, शौचालय और बैरकों में प्रकाश व स्वच्छता की स्थिति की बारीकी से जांच की। उन्होंने थाना प्रभारी और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रशिक्षण ले रहे जवानों को दी जाने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। विशेषकर मेस में भोजन की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। एएसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस बल की मजबूती उनके बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है, जिसके लिए बुनियादी सुविधाओं का मानक के अनुरूप होना आवश्यक है। औपचारिक निरीक्षण के बाद एएसपी ने रिक्रूट आरक्षियों के साथ बैठक कर उनसे सीधा संवाद स्थापित किया। अनौपचारिक वातावरण में हुई इस बातचीत के दौरान उन्होंने जवानों से उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना तथा मौके पर ही उनके समाधान के लिए संबंधित को निर्देशित किया। उन्होंने नए आरक्षियों को प्रेरित करते हुए कहा कि पुलिस सेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का बड़ा उत्तरदायित्व है, जिसे अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा के साथ ही निभाया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान थाने की सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। एएसपी ने जवानों को जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार और कानून के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का मंत्र दिया। इस दौरान थाने के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

49 लाख की रकम से दामोदरी पोखरा बाईपास मार्ग का हुआ शुभारंभ

सड़क बनने से शहरवासियों के साथ ही आम लोगों को मिलेगी सहूलियत

निचलौल।

पूजन के बाद सड़क बनने के लिए कार्य हुआ शुरू

नगर पंचायत निचलौल के हरेंडीह वार्ड स्थित सिसवा व चिउटहा रोड को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण दामोदरी पोखरा बाईपास मार्ग के निर्माण कार्य का रविवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। चेयरमैन शिवनाथ मद्धेशिया ने वैदिक मंत्रोचार के बीच पूजन-अर्चन कर कार्य की शुरुआत की गई। इस दौरान वार्ड में उत्साह का माहौल रहा और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। चेयरमैन शिवनाथ मद्धेशिया ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र का समग्र विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से न केवल सिसवा और चिउटहा मार्ग के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा, बल्कि लोगों को आवागमन में भी बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि नगर पंचायत द्वारा विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी और सभी योजनाओं को समयबद्ध व गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ बनी रहे। बता दें कि लगभग 400 मीटर लंबी इस सड़क का निर्माण पंडित दीनदयाल नगर विकास योजना के अंतर्गत करीब 49 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है। इस मार्ग के बन जाने से लोगों को आवागमन सुगम होगा और लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में चेयरमैन प्रतिनिधि सुनील मद्धेशिया मुन्ना, सभासद संजय पाण्डेय, शमशाद आलम, रंजीत चौरसिया, महेंद्र मिश्रा, रमेश, दिनेश कुमार, विवेक गुप्ता, नरेश यादव आदि मौजूद रहें।

इमामचौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी की पहल, यूपी बोर्ड 2026 के टॉपर्स होंगे सम्मानित

गोरखपुर। इमामचौक मुतवल्ली एक्शन कमेटी, गोरखपुर के तत्वावधान में यूपी बोर्ड परीक्षा-2026 में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं के सम्मान के लिए जल्द ही भव्य 'प्रतिभा सम्मान समारोह' आयोजित किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल्लाह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन कमेटी के संरक्षक एवं वरिष्ठ काउन्सलर खैरूल बशर के सानिध्य में संपन्न होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। संरक्षक खैरूल बशर ने बताया कि इस समारोह में केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स ही नहीं, बल्कि अन्य विभिन्न क्षेत्रों की परीक्षाओं में सफल प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को उपहार देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाएगी। कमेटी अध्यक्ष अब्दुल्लाह ने बताया कि सम्मान प्राप्त करने के इच्छुक छात्र-छात्राएं अपनी जानकारी एवं पंजीकरण के लिए गोरखपुर के बक्शीपुर स्थित हुसैनिया मदरसा बिल्डिंग (फाइन ऑफसेट प्रिंटर्स) पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने क्षेत्र के सभी मेधावी विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

ग्रेट निकोबार पर राहुल के सवालों से डरी सरकार, कांग्रेस ने दावों के बीच कहा- सदन में हो चर्चा

नई दिल्ली । ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस का दावा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 28 अप्रैल 2026 के दौरे से सरकार घबरा गई है और डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। पार्टी ने पर्यावरण, आदिवासी अधिकारों और पारदर्शिता के मुद्दे उठाते हुए इस पूरी परियोजना पर संसद में विस्तार से चर्चा कराने की मांग की है ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना को लेकर देश की राजनीति अचानक गरमा गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर बहुत तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया ग्रेट निकोबार दौरे के बाद से सरकार पूरी तरह से घबरा गई है। पार्टी का कहना है कि सरकार अब अपनी कमियां छिपाने और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने रविवार को इस प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण, आदिवासियों के अधिकार, पारदर्शिता और सुरक्षा से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं जाहिर की है। पार्टी ने बहुत सख्ती से कहा है कि इन सभी अहम मुद्दों पर संसद के एक मंच पर विस्तार से बहस होनी चाहिए।कांग्रेस का मानना है कि यह विकास योजना देश की सुरक्षा और पर्यावरण के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। पार्टी चाहती है कि देश की जनता को पता चले कि इस विकास योजना से प्रकृति और स्थानीय लोगों को कितना नुकसान होने वाला है।

जयराम रमेश ने राहुल गांधी के दौरे पर क्या दावा किया?

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 28 अप्रैल 2026 को राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार का एक बहुत ही असरदार दौरा किया था। इस दौरे के बाद सरकार घबरा गई और तीन दिन बाद 1 मई 2026 को आनन-फानन में एक प्रेस नोट जारी कर दिया।

रमेश का आरोप है कि सरकार ऐसा करके आने वाली बड़ी पर्यावरणीय तबाही से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने 1 मई के सरकारी प्रेस नोट का एक बहुत ही विस्तृत और कड़ा जवाब भी अपनी तरफ से सार्वजनिक रूप से साझा किया है।

जयराम रमेश ने सरकार से क्या सवाल पूछे?

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार की नीयत पर सीधे सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी के दौरे से बौखलाई सरकार ने अचानक इस बड़े प्रोजेक्ट पर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। उनका कहना है कि सरकार असल मुद्दों से भाग रही है और पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आ गई है। उन्होंने इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरतने और संसद के भीतर सरकार की जवाबदेही तय करने की पुरजोर मांग की है।

चुनाव नतीजे आज- बंगाल में कौन मारेगा बाजी, असम में बीजेपी, तमिलनाडु में डीएमके की हैट्रिक या केरलम में कांग्रेस की होगी वापसी?

नई दिल्ली।

पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आज जनादेश का दिन है. 15 मार्च को चुनावी ऐलान के बाद 50 दिनों तक जो सियासी घमासान चला, उसके बाद बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आएंगे. मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी.सबकी निगाहें 294 सीटों वाले बंगाल पर होंगी, जहां ज्यादातर एग्जिट पोल द्वारा 15 साल से सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर से सियासी पारा चरम पर है. बंगाल के पहले चरण में रिकॉर्ड 93% और दूसरे चरण में 90 फीसदी मतदान ने भी मुकाबला बेहद दिलचस्प बना दिया है. 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की बात करें 10 सालों से एमके स्टालिन की अगुवाई में सत्तारूढ़ डीएमके गठबंधन की हैट्रिक के आसार ज्यादातर एग्जिट पोल ने जताए हैं. असम में बीजेपी हैट्रिक तो केरलम में कांग्रेस 10 साल के वनवास के बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद देख रही है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम समेत पांच राज्यों के चुनावी नतीजे आज घोषित होंगे. तमिलनाडु, असम, केरलम और पुडुचेरी के नतीजे भी आज घोषित होंगे.

बंगाल विधानसभा चुनाव- बीजेपी, टीएमसी में कांटे की टक्कर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फाल्टा सीट पर दोबारा मतदान के आदेश के बाद 293 सीटों के नतीजे आएंगे.देखना होगाकि क्या लेफ्ट की तरह ही तृणमूल कांग्रेस को 15 साल सरकार के बाद वहां चौथी बार सरकार बनाने का जनादेश मिलता है या फिर बीजेपी बड़ा बदलाव लेकर आएगी. बंगाल में द्विपक्षीय मुकाबले में 2021 विधानसभा चुनाव लेफ्ट और कांग्रेस शून्य पर पहुंच गए थे. बंगाल के में 77 केंद्रों पर मतगणना होगी, जो पहले घोषित 87 और 2021 के 108 केंद्रों की तुलना में कम है. काउंटिंग सेंटर पर त्रिस्तरीय सुरक्षा इंतजाम है.

भवानीपुर में ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी

मतगणना स्थल पर चुनाव आयोग द्वारा जारी क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र से ही एंट्री होगी. चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षकों को छोड़कर कोई भी काउंटिंग सेंटर में मोबाइल नहीं ले जा सकेगा.कोलकाता के 11 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल, सखावत मेमोरियल स्कूल, नेताजी इंडोर स्टेडियम आंबेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी और सेंट थॉमस बॉयज स्कूल में होगी. भवानीपुर विधानसभा सीट पर सीएम ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी से है.

कांग्रेस, लेफ्ट भी मैदान में

बंगाल चुनाव में टीएमसी ने 291 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और दार्जिलिंग में 3 सीटें भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा को गठबंधन के तहत दी थी. बीजेपी, कांग्रेस और वाम मोर्चा ने सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ा. हुमायूं कबीर की एजेयूपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार उतारे. बीजेपी से दिलीप घोष, निशिथ प्रमाणिक, अग्निमित्रा पॉल, रूपा गांगुली जैसे नेता चुनाव लड़े हैं. टीएमसी प्रत्याशियों में फिरहाद हकीम, उदयन गुहा, कुणाल घोष, मदन मित्रा शामिल हैं.

केरलम में कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें

140 सीटों वाली केरल विधानसभा चुनाव में इस बार 10 सालों से सत्ता में काबिज वाम मोर्चा (एलडीएफ), कांग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) और भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए में त्रिकोणीय मुकाबला रहा. 9 अप्रैल को एक चरण के मतदान में करीब 80 फीसदी वोटिंग हुई. केरल में सुबह 8 बजे से 43 जगहों पर 140 मतगणना केंद्रों के जरिये काउंटिंग होगी.ज्यादातर एग्जिट पोल में यूडीएफ के सत्ता में लौटने और लेफ्ट के सरकार गंवाने के आसार दिख रहे हैं. बहुमत के 71 के आंकड़े से अधिक यूडीएफ को 80 से 85 सीटें मिलने के संकेत एग्जिट पोल ने दिए हैं. 2016 में नेमोम विधानसभा सीट जीतने वाली बीजेपी 2021 में शून्य पर रही, लेकिन इस बार एनडीए को 3 से 14 तक सीटों का अनुमान एग्जिट पोल में है. केरल में कुल पड़े वोटों में 1.36 फीसदी पोस्टल बैलेट हैं, जिनके परिणाम भी अहम हैं.

क्रूज हादसे में 13 मौतें, आज मिले चाचा-भतीजे के शव

जबलपुर । यह एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है हमें रेमेडी (मुआवजा) नहीं, जस्टिस चाहिए। इसके लिए सारा का सारा एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अभी तक कितने ऑफिसर अरेस्ट किए गए, कितने सस्पेंड किए गए? बोट ऑपरेटर कहां है? उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? यह आक्रोश है क्रूज हादसे में जान गंवाने वाले कामराज के दोस्त और सहकर्मी का। उन्होंने सीधे तौर पर टूरिज्म डिपार्टमेंट को कटघरे में खड़ा किया और अफसरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि कामराज की सैलरी 1 लाख रुपए थी, ऐसे में सहायता राशि से नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हुई है, जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक न्याय अधूरा रहेगा। वहीं आज सुबह 9.40 बजे कामराज आर. का शव निकाला गया। इससे पहले सुबह करीब 6 बजे उनके 8 साल के भतीजे मयूरन की डेडबॉडी मिली थी। वह त्रिची (तमिलनाडु) से आया था। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है।

दिल्ली में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग, 9 की मौत

इनमें डेढ़ साल का बच्चा शामिल; 15 लोग बचाए गए, एसी में ब्लास्ट की आशंका

नई दिल्ली । दिल्ली के शाहदरा इलाके के विवेक विहार में एक चार मंजिला बिल्डिंग में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 पुरुष, 4 महिलाएं और एक डेढ़ साल का बच्चा शामिल है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक, उन्हें सुबह करीब 3.47 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। 4 घंटों की मशक्कत के बाद सुबह करीब 8 बजे आग पर काबू पाया गया। बिल्डिंग के अंदर फंसे 10 से 15 लोगों को बचाया गया। इनमें दो लोग घायल हुए हैं। मृतकों के शव बिल्डिंग के अलग-अलग फ्लोर से बरामद किए गए। स्थानीय पार्षद पंकज लूथरा ने बताया कि कुछ शव इतने बुरे तरह जल चुके हैं कि सिर्फ कंकाल बचा है। डीएनए टेस्ट के बाद ही मृतकों का पता चल पाएगा। हादसे को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि एसी में धमाके के बाद आग फैली। फिलहाल अधिकारियों की तरफ से असली कारण की पुष्टि नहीं हुई है।

9 मृतकों के नाम सामने आए, लेकिन पहचान मुश्किल

दिल्ली पुलिस के अनुसार, बिल्डिंग के पहले फ्लोर से 1 शव, दूसरे फ्लोर से 5 शव और सीढ़ियों से 3 शव मिले, जहां दरवाजा बंद था। आशंका है कि लोगों ने छत पर भागकर जान बचाने की कोशिश की थी। दूसरे फ्लोर पर मिले मृतकों की पहचान अरविंद जैन (60), उनकी पत्नी अनीता जैन (58), बेटे निशांत जैन (35), बहू आंचल जैन (33) और डेढ़ साल के पोते आकाश जैन के रूप में हुई। तीसरे फ्लोर पर नितिन जैन (50), उनकी पत्नी शैले जैन (48) और बेटे सम्यक जैन (25) मृत पाए गए। पहले फ्लोर पर शिखा जैन (45) का शव मिला, जबकि उनके पति नवीन जैन (48) घायल हो गए। स्थानीय पार्षद पंकज लूथरा ने बताया कि उन्होंने मृतकों के शव देखें हैं। इनमें कौन से शव पुरुष के हैं और कौन सी महिला के, इसकी पहचान करना भी मुश्किल है।

बिल्डिंग के पिछले हिस्से से ज्यादातर शव मिले

दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि चार मंजिला बिल्डिंग के हर फ्लोर पर दो 4बीएचके फ्लैट हैं। आग बिल्डिंग के पिछले हिस्से में लगी थी और वहीं सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 6 फ्लैट्स का सामान जल गया। DFS के मुताबित, खिड़कियों और बालकनी पर ग्रिल और लोहे की रॉड लगी थीं, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आई। फिर भी करीब 15 लोगों को बचाया। इनमें से एक व्यक्ति करीब 30फीसदी तक जल गया था, जिसे इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

भारतीय मीडिया पर हो रहा हमला- कांग्रेस ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जताई चिंता

नई दिल्ली । तीन मई का दिन पूरी दुनिया में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य मकसद प्रेस की आजादी और पत्रकारों के अधिकारों की बात करना है। लेकिन इस बार इस मौके पर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया है। भारत में मीडिया की आजादी को लेकर कांग्रेस ने गहरी चिंता जताई है और इसे देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी बताया है। रविवार को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने भारत में प्रेस की आजादी की मौजूदा स्थिति पर तीखा हमला बोला है।

कांग्रेस ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 का हवाला देते हुए अपनी बात रखी है। इस सूचकांक में भारत को 157वें स्थान पर रखा गया है। रैंकिंग की इस सूची में भारत को बहुत ही गंभीर श्रेणी में डाला गया है। इसी रैंकिंग को लेकर कांग्रेस ने देश में सच बोलने वालों की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए सरकार को घेरा है और पत्रकारों के समर्थन में बात कही है। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि एक स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की असली आवाज होती है। पार्टी का सीधा आरोप है कि आज के समय में लोकतंत्र की इस आवाज पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत के 157वें स्थान पर खिसकने और गंभीर श्रेणी में आने पर चिंता जाहिर की। कांग्रेस ने कहा कि वो हर उस निडर आवाज के साथ मजबूती से खड़ी है, जो सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत रखती है। इसके साथ ही पार्टी ने उन सभी पत्रकारों का समर्थन किया है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

बंगाल चुनाव - मतगणना के लिए 432 आब्जर्वर तैनात, उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा निगरानी

कोलकाता। बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी अब करीब है। सोमवार को राज्य की 293 सीटों (फलता को छोड़कर) पर होने वाली मतगणना को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आयोग ने शनिवार को काउंटिंग आब्जर्वर्स की आधिकारिक सूची जारी कर दी है, जिसके तहत कुल 432 पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है।

उत्तर 24 परगना में सुपर विजिलेंस

आयोग की सूची के अनुसार, उत्तर 24 परगना जिला इस बार मतगणना के केंद्र में रहने वाला है। यहां की 33 सीटों के लिए सर्वाधिक 49 काउंटिंग आब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके ठीक बाद दक्षिण 24 परगना का नंबर आता है, जहां 31 सीटों के लिए 45 पर्यवेक्षकों की भारी-भरकम टीम तैनात की गई है। हालांकि, फालता सीट पर गणना टलने के कारण इस संख्या में मामूली फेरबदल की संभावना है।

अलीपुरद्वार में सबसे कम अमला

जहां एक ओर बड़े जिलों में आब्जर्वर्स की फौज उतारी गई है, वहीं अलीपुरद्वार में सबसे कम पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। यहां की पांच सीटों के लिए केवल छह आब्जर्वर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी कोलकाता की बात करें तो यहां की 11 सीटों के लिए 12 पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे।

165 अतिरिक्त पर्यवेक्षक भी संभालेंगे मोर्चा

इस बार आयोग ने उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है जहां एक से अधिक मतगणना कक्ष हैं। ऐसे केंद्रों के लिए 165 अतिरिक्त काउंटिंग आब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, जो पहले से तैनात पर्यवेक्षकों की सहायता करेंगे।

सुरक्षा का घेरा पर कमरे में प्रवेश नहीं

मतगणना केंद्रों के बाहर की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए 77 पुलिस आब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है। आयोग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ये पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष के भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। इनका काम बाहरी परिसर में समन्वय और व्यवस्था बनाए रखना होगा।

शुभेंदु बोले- मतगणना से पहले अधिकारियों की ड्यूटी जानकारी लीक, आयोग से की कार्रवाई की मांग

कोलकाता । पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी अपनी ड्यूटी, स्थान और जिम्मेदारियों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी विभागीय संगठनों और संघों के साथ साझा कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले पर तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे सोमवार को होने वाली मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर असर पड़ सकता है और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता खतरे में आ सकती है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मेरे संज्ञान में यह बात आई है कि मतगणना के दिन ड्यूटी के लिए तैनात कई अधिकारी कथित तौर पर अपनी ड्यूटी का विवरण, स्थान और

पदनाम अपने-अपने विभागीय संगठनों और संघों को बता रहे हैं। मुझे यह जानकारी मिली है कि कुछ स्क्रीनशॉट और सूचियां प्रसारित की जा रही हैं, जिनमें अधिकारी अपनी चुनाव ड्यूटी की जानकारी स्वेच्छा से या किसी दबाव में भर रहे हैं। इसमें मतगणना प्रक्रिया के दौरान उनकी विशिष्ट भूमिकाओं का विवरण भी शामिल है।

भाजपा ने ईसी से की शिकायत

शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट के साथ कुछ व्हाट्सएप मैसेज के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव संबंधी नियमों का एक गंभीर उल्लंघन है। भाजपा नेता ने कहा, मतगणना प्रक्रिया की पवित्रता और विश्वसनीयता, इसमें शामिल कर्मियों की तैनाती की गोपनीयता पर निर्भर करती है। इस गोपनीयता का कोई भी उल्लंघन परिणामों की निष्पक्षता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जब किसी अधिकारी की तैनाती का विशिष्ट विवरण किसी राजनीतिक झुकाव वाले संगठन या संघ को पता चल जाता है, तो इससे अनावश्यक राजनीतिक प्रभाव और दबाव (धमकी) की गुंजाइश बन जाती है। उन्होंने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मामले का तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। भाजपा नेता ने अपील की है कि अधिकारियों को किसी भी संगठन या संघ के साथ अपनी मतगणना ड्यूटी साझा करने से रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाएं और इस तरह की जानकारी जुटाने वाले संगठनों की जांच कराई जाए।

अहीरवाल में सैनी की राजनीतिक इंजीनियरिंग, राव इंद्रजीत व राव नरबीर के बीच सियासी संतुलन

चंडीगढ़ ।

अहीरवाल की राजनीति में शनिवार को नए राजनीतिक समीकरण बनते दिखे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं था, बल्कि पार्टी में पिछले कई साल से दक्षिण हरियाणा के लिए चली आ रही परंपरा से अलग एक राजनीतिक इंजीनियरिंग का एक नया प्रयोग था। अपने एक दिन के दौरे में सबसे पहले उन्होंने राव इंद्रजीत के खिलाफ 319 दिन से चले आ रहे जनता के गुस्से को कैबिनेट में अपने साथी राव नरबीर की मौजूदगी में शांत कराया और फिर सीधे रामपुरा हाउस पहुंच राव इंद्रजीत के घर पर भोजन कर अहीरवाल की राजनीति में शक्ति संतुलन की नई तस्वीर का खाका भी खींचा। नायब सिंह सैनी का यह कदम इस बात का संकेत है कि लोग उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। वे भाजपा के पूर्व सीएम की नीति से अलग चलते हुए सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रख रहे हैं। सीएम सैनी का रेवाड़ी के गांव गोकलपुर का दौरा पहले से ही प्रस्तावित था। गांव के प्राचीन शिव मंदिर में आयोजित भंडारे व शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचने से पहले वे राव नरबीर के साथ रामगढ़-भगवानपुर में 319 दिनों से चल रहे धरने पर पहुंचे। यह आंदोलन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों के आक्रोश से उपजा था, जिसमें उन पर वादाखिलाफी का आरोप था।

मुख्यमंत्री ने राव नरबीर सिंह के साथ पहुंचकर न केवल संवाद स्थापित किया, बल्कि स्टेडियम और आयुर्वेदिक कॉलेज जैसी विकासपरक घोषणाओं के माध्यम से आंदोलन को 319वें दिन विराम दिलाया। इस पूरे घटनाक्रम में धरने के समापन का श्रेय राव नरबीर को मिलना, स्थानीय शक्ति-संतुलन में उनके पुनर्वास की तरह देखा जा रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री का रामपुरा स्थित राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर जाना, जहां भोजन और विस्तृत राजनीतिक चर्चा हुई, अपने आप में अभूतपूर्व था।

यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने उनके आवास पर जाकर सीधा संवाद स्थापित किया हो। इससे पहले राव इंद्रजीत जब कांग्रेस में थे तो तब भी कोई सीएम उनके घर नहीं गया था और न ही भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री। इस मुलाकात में प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया की उपस्थिति ने इस राजनीतिक संदेश को और अधिक संस्थागत स्वरूप प्रदान किया। यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि मुख्यमंत्री अहीरवाल के सबसे प्रभावशाली चेहरे को पूरी तरह अलग-थलग रखने के बजाय उन्हें मुख्यधारा में बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहा है।

दक्षिण हरियाणा में पार्टी के अंदर राव इंद्रजीत ही एक ऐसे नेता हैं, जो समय-समय पर पार्टी को इशारों में सवाल उठाते रहे हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित पांच शहरों के विरोध जैसे बयानों ने उनकी स्वतंत्र राजनीतिक स्थिति को और स्पष्ट किया था। राव इंद्रजीत कई बार अपने भाषणों में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में सैनी पहुंचना और साथ में लंच करना दोनों नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकियों और बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। यही नहीं रेवाड़ी और धारूहेड़ा के निकाय चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर उनके उम्मीदवारों को टिकट देना और उनकी करीबी मानेसर की निर्दलीय मेयर को भाजपा में शामिल कराने की मंजूरी देना कहीं न कहीं यह बताता है कि मुख्यमंत्री और राव इंद्रजीत की बढ़ती नजदीकियों के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर, यह दौरा राव नरबीर सिंह की राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी अप्रत्यक्ष रूप से मजबूती देता है, क्योंकि आंदोलन समापन में उनकी भूमिका को प्रमुखता मिली। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि राव नरबीर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री का संतुलनकारी रुख दोनों पक्षों को साधने की रणनीति को दर्शाता है।

हमारे सीएम सफेद मूठ छोड़ने वाले सिद्ध पुरुष - राव इंद्रजीत

केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सफेद मूठ छोड़ने वाला सिद्ध पुरुष बताया। राव ने कहा, पुराने समय में सिद्ध पुरुष दो प्रकार के माने जाते थे। एक वे जो तांत्रिक साधनाओं और कथित काली विद्या से जुड़े होते हैं जबकि दूसरे वे होते हैं जो राम-राम का जाप करके सकारात्मक शक्ति प्राप्त करते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को सफेद मूठ से जोड़ते हुए उन्हें जनहित में काम करने वाला और लोगों की भलाई करने वाला नेता बताया।